

भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 364

मंगलवार, 19 अगस्त, 2025/28 श्रावण, 1947 (शक) को उत्तरार्थ

डेयरी क्षेत्र के लिए नई बहुराज्यीय सहकारी समितियां

***364. श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया:**
श्रीमती रूपकुमारी चौधरी:

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) डेयरी क्षेत्र के लिए तीन नई बहुराज्यीय सहकारी समितियों की स्थापना का ब्यौरा और उनके विशिष्ट कार्य क्या हैं और उक्त समितियों के कब तक कार्यात्मक होने की संभावना है;
- (ख) किसानों की आय बढ़ाने और सतत पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए उक्त समितियां किस प्रकार लाभकारी हैं;
- (ग) महाराष्ट्र सहित देश भर में अधिक एकीकृत और आत्मनिर्भर डेयरी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने के लिए सहयोग बढ़ाने हेतु कार्यान्वित किए जा रहे विशिष्ट नीतिगत उपायों और संरचनात्मक परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है;
- (घ) इस सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सहकारिता मंत्रालय, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) का सहयोगात्मक ढांचा और संबंधित भूमिकाएं क्या हैं;
- (ङ) कर्नाटक और विशेष रूप से चिकबल्लापुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की डेयरी सहकारी समितियों के लिए नाबार्ड द्वारा की गई पहलों का ब्यौरा क्या है; और
- (च) क्या सरकार का विचार जलगांव लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र जैसे क्षेत्रों में इस योजना के अंतर्गत प्रायोगिक पहलों को बढ़ावा देने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) से (च): सदन के पटल पर एक विवरणी रखी गई है ।

श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया और श्रीमती रूपकुमारी चौधरी द्वारा “डेयरी क्षेत्र के लिए नई बहुराज्यीय सहकारी समितियां” के संबंध में पूछे गए दिनांक 19 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 364 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (घ): डेयरी भारत में कृषि का सबसे बड़ा उत्पाद है जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 3.5% का योगदान (नेशनल एकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स के अनुसार) दे रहा है। वर्ष 2023-24 में भारत का दुग्ध उत्पादन 239.3 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) था जो वैश्विक उत्पादन का 25% था। उत्पादक स्तर पर लगभग 88 MMT (37%) का उपभोग किया गया और 150 MMT विपणन-योग्य अधिशेष था। इस अधिशेष में से मात्र 32% (47 MMT) ही संगठित क्षेत्र द्वारा दुग्ध संबंधी कार्य किया जा रहा है जबकि शेष 68% (102 MMT) दुग्ध संबंधी कार्य असंगठित क्षेत्र द्वारा किया जा रहा है। संगठित क्षेत्र में किए जा रहे दुग्ध संबंधी कार्यों में सहकारी क्षेत्र द्वारा 56% (26 MMT) दुग्ध संबंधी कार्य किया जाता है।

असंगठित क्षेत्र में किए जाने वाले दुग्ध संबंधी कार्य मिलावट, डेयरी किसानों का शोषण और मूल्य संवर्धन की कमी जैसे अनेक समस्याओं से ग्रसित हैं। इन मुद्दों के समाधान और सहकारी डेयरी परितंत्र को सशक्त समस्याओं को दूर करने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने श्वेत क्रांति 2.0 लॉन्च किया है जो सहकारिता आधारित एक पहल है जो डेयरी क्षेत्र में संधारणीयता और चक्रीयता लाते हुए सहकारी कवरेज में विस्तार, रोजगार सृजन और महिला सशक्तीकरण को लक्षित है। पांचवे वर्ष के अंत, अर्थात् वर्ष 2028-29 तक सहकारी समितियों द्वारा दुग्ध प्रापण 1007 लाख किलोग्राम प्रति दिन पहुंचना लक्षित है।

जहां श्वेत क्रांति 2.0 के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया का विमोचन 19 सितंबर, 2024 को किया गया वहीं दिनांक 25.12.2024 को श्वेत क्रांति 2.0 को निम्नलिखित रणनीतियों के माध्यम से अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए औपचारिक रूप लॉन्च किया गया:

- i. 75,000 नई डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना द्वारा डेयरी सहकारी समितियों के कवरेज में विस्तार करना।
- ii. मौजूदा 46,422 डेयरी सहकारी समितियों का सशक्तीकरण।
- iii. निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए तीन विशिष्ट बहुराज्य सहकारी समितियों की स्थापना द्वारा डेयरी क्षेत्र में संधारणीयता और चक्रीयता लाना:-

(क) पशुचारा, खनिज मिश्रण और अन्य तकनीकी इनपुट्स की आपूर्ति करना।

(ख) सहकारी प्रयासों द्वारा जैविक खाद उत्पादन और संधारणीय अपशिष्ट का उपयोग को प्रोत्साहित करना, प्राकृतिक खेती और पर्यावरण अनुकूल मृदा निविष्टियों और राष्ट्रीय

संधारणीयता लक्ष्यों की बढ़ती मांगों के प्रत्युत्तर में जैविक उर्वरकों एवं बायोगैस में परिवर्तित करने के लिए गोबर और कृषि अपशिष्ट के उपयोग द्वारा चक्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान देना ।

(ग) मृत पशुओं के हड्डियों, खाल और सींगों के प्रबंधन के लिए ।

इन उपायों का लक्ष्य डेयरी किसानों के आय में वृद्धि करना, आपूर्ति श्रृंखला में दूध की गुणवत्ता और बचाव में सुधार, ग्रामीण रोजगार और संधारणीय व सहकारिता आधारित विकास मॉडल के अंतर्गत देश भर में अधिक एकीकृत और स्वावलंबी डेयरी परितंत्र का सृजन करना है । प्रभावी और समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने डेयरी और पशुपालन विभाग तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के समन्वय से दिनांक 19.09.2024 को मानक प्रचालन प्रक्रिया (मार्गदर्शिका) का विमोचन किया है जिसमें सभी हितधारकों की भूमिका, लक्ष्य और समय-सीमा की रूपरेखा दर्शायी गई हैं । इस प्रकार यह पहल 'सरकार के संपूर्ण दृष्टिकोण' का अनुपालन करते हुए कार्यान्वित किया जाएगा ।

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और नाबार्ड के बीच रणनीतिक सहयोग का लक्ष्य नाबार्ड की वित्तीय क्षमता के साथ राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की तकनीकी विशेषज्ञता के मिश्रण द्वारा एक संधारणीय और जलवायु अनुकूल डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देना है । इसमें अवसंरचना, मूल्य श्रृंखला का सशक्तीकरण, सहकारी क्षमता वर्धन और समावेशी विकास के संवर्धन के लिए बाजार पहुंच में सुधार हेतु हरित वित्तीयन मॉडल का विकास करना शामिल है ।

श्वेत क्रांति 2.0 पहल को वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान पांच वर्षों के लिए कार्यान्वित किया जाएगा ।

(ड): नाबार्ड ने कर्नाटक के डेयरी क्षेत्र में 10 किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) को प्रोत्साहित किया है जिसमें 2,901 शेयरधारक शामिल हैं, जिसमें से 2,538 छोटे और सीमांत किसान हैं और 1,069 महिला किसान हैं । शेयर पूंजी के रूप में कुल ₹ 24.85 लाख जुटाया गया है और क्रेडिट सहायता के रूप में ₹55 लाख तथा क्रेडिट गारंटी कवर के रूप में ₹38.25 लाख प्रदान किया गया है । यद्यपि, चिकबल्लापुर में डेयरी सहकारी समितियों के अधीन किसी FPOs को प्रोत्साहित नहीं किया गया है । इसका ब्योरा संलग्नक पर प्रस्तुत है ।

(च): पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD) के संशोधित राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD) के अधीन जलगांव दुग्ध संघ ने वर्ष 2025-26 में राज्य सरकार को 117 नई डेयरी सहकारी समितियों (DCSs) की स्थापना का प्रस्ताव देते हुए इस योजना के अधीन वित्तीय सहायता का निवेदन किया है ।

कृषक उत्पादक संगठन (FPO) – चिक्कबल्लापुर क्षेत्र

क्रम संख्या	एफपीओ का नाम	स्थिति (सक्रिय / निष्क्रिय)	परियोजना (पूर्ण / प्रगति पर)	किस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत	फंड	पीओपीआई का नाम	शेयरधारकों की संख्या	लघु एवं सीमांत किसानों की संख्या	महिला किसानों की संख्या	व्यावसायिक गतिविधियाँ	संग्रहित शेयर पूंजी (लाख में)	इक्विटी अनुदान सहायता (लाख में)	कुल प्राप्त ऋण (लाख में)	ऋण गारंटी सहायता (हाँ/नहीं) – यदि हाँ, तो विवरण (लाख में)	अन्य कोई सहायता (यदि हो)
1	प्रगति फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड	सक्रिय	पूर्ण	कंपनी अधिनियम	Produce	RIDA	500	472	326	सब्जी, डेयरी, कमोडिटी	6	NIL	10	NIL	—
2	जवारी एममे ताली अभिवृद्धि मट्टु हालु उत्पादक संघ	निष्क्रिय	पूर्ण	सहकारी समिति अधिनियम	Produce	फ्यूचर ग्रीन्स संस्था	451	354	450	डेयरी और मूल्य वर्धित उत्पाद	6	NIL	NIL	NIL	—
3	सदरहल्ली डेयरी फार्म प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड	निष्क्रिय	पूर्ण	कंपनी अधिनियम	Produce	व्यक्ति विकास केंद्र	84	84	40	दूध संग्रहण और प्रसंस्करण	0.87	NIL	NIL	NIL	—
4	श्री प्रभुलिंगेश्वर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड	सक्रिय	प्रगति पर	कंपनी अधिनियम	PODF-ID	विकासना (संकल्प RDS से विकासना)	400	290	50	इनपुट, दूध संग्रहण केंद्र	4.9	NIL	45	हाँ, ₹38.25 लाख	—
5	ग्रामीण भारत डेयरी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड	सक्रिय	प्रगति पर	कंपनी अधिनियम	PODF-ID	जय संतोषी माता ग्रामीण विकास	400	320	20	डेयरी क्रय, उर्वरक, पशु आहार, बीज	0.55	NIL	NIL	NIL	—
6	बायरसिद्धेश्वरा एफपीसीएल	सक्रिय	प्रगति पर	कंपनी अधिनियम	PODF-ID	VOICE	100	80	20	इनपुट – पशु आहार, चारे के बीज की आपूर्ति; आउटपुट – दूध का क्रय-विक्रय	0.12	NIL	NIL	NIL	—
7	कृषिनिरंतर एफपीसीएल	सक्रिय	प्रगति पर	कंपनी अधिनियम	PODF-ID	प्रगति मित्र नॉर्थ कन्नारा एफपीसीएल	300	260	10	इनपुट – पशु आहार, चारा, जैविक खाद, पूरक, साइलेंज, पीवीसी पाइप; आउटपुट – दूध	3	NIL	NIL	NIL	—

										एवं फार्म यार्ड मैन्योर					
8	बीएस-4जी डेयरी एफपीसीएल	सक्रिय	प्रगति पर	कंपनी अधिनियम	PODF- ID	नवा निर्मल ग्रामीण विकास सोसायटी	416	320	133	इनपुट – उर्वरक बिक्री, पशु आहार बिक्री; आउटपुट – दूध बिक्री, दूध संग्रहण व विपणन	3.21	NIL	NIL	NIL	—
9	चडाचना समुदाय एफपीसीएल	—	प्रगति पर	कंपनी अधिनियम	PODF- ID	समुदाय संपन्नमूल अभिवृद्धि संस्था (CRDS)	110	110	10	आउटपुट – डेयरी, खाद्य उत्पाद और ग्रामीण मार्ट	0.1	NIL	NIL	NIL	—
10	गोलक इम्यून प्रोडक्ट्स एफपीसीएल	—	प्रगति पर	कंपनी अधिनियम	PODF- ID	विशाल	250	248	10	इनपुट – पशु आहार; आउटपुट – प्याज व्यापार, दूध संग्रहण एवं आपूर्ति (योजना में)	0.1	NIL	NIL	NIL	—
कुल	—	—	—	—	—	—	2901	2538	1069	—	24.85	—	55	38.25	—

चिक्कबल्लापुर क्षेत्र में डेयरी सहकारी समितियाँ

क्रम संख्या	एफपीओ का नाम	स्थिति (सक्रिय / निष्क्रिय)	परियोजना (पूर्ण / प्रगति पर)	किस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत	फंड	पीओपीआई का नाम	शेयरधारकों की संख्या	लघु एवं सीमांत किसानों की संख्या	महिला किसानों की संख्या	व्यावसायिक गतिविधियाँ	संग्रहित शेयर पूंजी (लाख में)	इक्विटी अनुदान सहायता / बीडीए (लाख में)	कुल प्राप्त ऋण (लाख में)	ऋण गारंटी सहायता (हाँ/नहीं) – यदि हाँ, तो विवरण (लाख में)	अन्य कोई सहायता (यदि हो)
—	NIL	—	—	—	—	—	NIL	—	—	—	NIL	—	NIL	—	—

